



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935

No. 649]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

**का. आ. 758(अ).**—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958(1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (5) के अनुसरण में केंद्रीय सरकारा एतद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2011 के का.आ. सं. 505(अ) के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण का अवार्ड प्रकाशित करती है ताकि नेशनल यूनियन ऑफ सीफेअरर्स ऑफ इंडिया, पोर्टब्लेयर बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अन्य द्वारा 2010 की रिट याचिका सं. 1276 में लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा अन्य को प्रस्तुत किए गए मांगों के चार्टर पर फैसला किया जा सके।

अवार्ड

रिटयाचिका सं 1276/2010 में दि. 19/11/2010 के कलकत्ता न्याय क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय (पोर्टब्लेयर में सर्किट बेंच) के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 31-05-2011 के का.आ. सं.1250(अ) के अनुसार जारी पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना प्राप्त होने पर, एकल व्यक्ति नयायाधिकरण की स्थापना की गई तथा इसने 11/8/2011 से कार्य करना आरंभ किया तथा कार्यवाहियों की अनुसूची के साथ उक्त के बारे में सभी संबंधित पक्षों को विधिवत सूचित किया गया था।

याचिकाकर्ता मेसर्स एनयूएसआई ने अपने शाखा प्रतिनिधि श्री धविन्दर राम द्वारा अभिवेदन कर अपना दावा प्रस्तुत किया गया तथा इसकी प्रतियां विधिवत रूप से प्रतिवादियों को उपलब्ध करवाई गई।

चौथे प्रतिवादी ने अपनी तथा अन्य तीन प्रतिवादियों की ओर से दावे का जवाब फाईल किया गया और विधिवत रूप से इसकी प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाई गई।

पक्षों द्वारा दिए गए दावे तथा अनुलग्नकों सहित जबाब/ उत्तर की जांच किए जाने पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय किया जाना तय किया है।

1. कर्मिंदल के लिए क्या यह न्यायोचित होगा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वे अपने आप खानपान की व्यवस्था करने लग जाएं।
2. क्या नेशनल मेरीटाइब बोर्ड करार दिनांक 14.02.2008 जिसपर कि प्रतिवादियों के हस्ताक्षर नहीं हैं क्या उसका प्रवर्तन प्रतिवादियों के विरुद्ध किया जा सकता है।
3. क्या एम एम बी करार के भी परिस्थितियों में कर्मिंदल द्वारा खानपान की व्यवस्था स्वयं करने की व्यवस्था देता है।
4. क्या खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा जलयानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन पर याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद अगस्त 2008 के पश्चात् खान-पान सेवाओं के अनुबंध को बढ़ाए जाने के संबंध में प्रतिवादी न्यायोचित हैं।
5. क्या सुव्यक्त करार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त का अनुमोदन न होने की दशा में 01.03.2008 से 28.02.2009 और 01.09.2008 से 20.02.2009 की अवधियों के लिए खाद्य सामग्री भत्ते हेतु एम.वी.नॉन कवरी और एम.वी. स्वराजद्वीप नामक दो जलयानों के कर्मी हकदार हैं।

“ अभिलेख सामग्री से यह प्रमाण लिया जा सकता है कि 18.01.2008 (अनुलग्नक पी-2 के अनुसार) से पहले कर्मियों को एम.वी. नॉन कवरी जलयान पर उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री और भोजन की गुणवत्ता पर शिकायतें नहीं की गई थी।

खान-पान का करार 14.09.2007 को आरंभ और 13.09.2008 को समाप्त हो गया ( अनुलग्नक पी-1 के अनुसार ) इसी तरह से 22.07.2008 से पहले जलयान एम.वी.स्वराज दीप के कर्मियों के ओर से शिकायतें नहीं थी। अनुलग्नक पी-5 से यह बात साफ है कि यानी एम.वी.नॉनकवरी की कार्यालयीन लॉगबुक से प्राप्त सार की कर्मियों की शिकायत पर पोत पर अन्य की उपस्थिति में मास्टर ने 29.09.2008 को खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया और पाया कि इसकी गुणवत्ता खराब है तथा यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है तथा समूची खाद्यसामग्री को हटा देने के आवश्यक अनुदेश जारी किए साथ ही यह पाया कि उस तरह के अनुदेश पहले भी कैंटिन मैनेजर को जारी किए गए थे जिनका पालन नहीं किया गया। इसके बाद 01.03.2008 को मास्टर ने कर्मियों से कहा कि वे कैंटिन मैनेजर से कोई सामग्री नहीं लेंगे तथा वे अपने से संबंधित कार्य का प्रबंधन स्वयं करेंगे। मास्टर ने कहा कि वह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अच्छी खाद्यसामग्री जारी की जाए तथा उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना उनकी मर्जी है तथा उसने आश्वासन दिया कि वह प्रतिवादी को सूचित कर देगा। इसके बाद पोत पर उसी दिन मास्टर के दौरे के दौरान यह देखा गया कि अरहर की दाल, नमक, आदि कैसी मर्द खराब गुणवत्ता की थी और खानपान अधिकारी को अनुदेश दिया गया था कि भंडार से खराब गुणवत्तावाली और जिन मर्दों को प्रयोग में लाए जाने की अंतिम तारीख निकल चुकी है उन सभी को हटा दिया जाए।

“अनुलग्नक-6 से पता चला कि चौथे प्रतिवादी को दिनांक 12.03.2008 की कार्यालयीन लॉग प्रविष्टि की एक प्रति एम.वी. दीप के मास्टर ने अग्रप्रेषित की। जैसा कि एम.वी.स्वराज दीप की कार्यालयीन लॉग बुक के उक्त सार से यह देखा जा सकता है कि गुणवत्ता पर कोई विशिष्ट बातें नहीं देखी गईं किंतु ब्रिज-विंग के विभाग के अपने विभाग प्रमुखों के साथ कर्मिंदल के सभी सदस्यों ने खान-पान की व्यवस्था अपने आप करने का अनुरोध किया, क्योंकि वे विद्यमान व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं थे।

“अनुलग्नक-7 एन.एम.वी करार है जिसमें सेवाशर्तों, भत्तों आदि से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों के अलावा पोत पर खान-पान की व्यवस्था स्वयं करने का मुद्दा निहित है, उक्त करार के खण्ड 28 में खान-पान भत्ते की व्यवस्था है जहां कि खान-पान की व्यवस्था स्वयं की जाती हो किंतु उस व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर्मिंदल को खान-पान की व्यवस्था स्वयं करने का अधिकार हो।

चौथे प्रतिवादी ने जवाब में इस बात पर बल दिया कि जलयान पर कर्मिंदल के सदस्यों को खाद्यसामग्री की वस्तुएं एन.एम.बी करार 2000 के अनुसार दी जा रही थीं किन्तु किसी भी पक्ष ने इसे न्यायाधिकरण के पक्ष में नहीं रखा है ताकि सेवा की विद्यमान शर्तों तथा निबंधनों को समझा जा सके। इस बात पर बल दिया गया था कि 01.05.2009 से ही पोत पर स्वयं खान-पान की प्रणाली का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी ने किया है। इसलिए 01.03.2009 से परिशोधित भुगतान (खाद्यसामग्री भत्ता) किया जाना न्यायोचित है और याचिकाकर्ता अनुमोदन की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए दावा नहीं कर सकता। इस विषयवस्तु पर 08.08.2008 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त अनुलग्नक-2 पर है जो बड़े महत्व का है, जिसमें याचिकाकर्ता खान-पान, कॉन्ट्रेक्टर तथा साथ ही प्रतिवादियों के अधिकारी उपस्थित थे, इससे पता चलता है कि यूनियन के प्रतिनिधियों में इस बात पर मतैक्य था कि वर्तमान अनुबंध के समाप्त होने के तत्काल उपरांत यानी दिनांक 01.09.2008 से खान-पान की व्यवस्था स्वयं किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बात पर भी सहमति थी कि यूनियन के प्रतिनिधि खान-पान की सामग्री अधिसूचित मात्रा तथा गुणवत्ता के अनुसार स्वीकार करेंगे और कॉन्ट्रेक्टर इस बात पर सहमत था कि अधिसूचना के अनुसार लम्बित अवधि के लिए वह खान-पान सामग्री की आपूर्ति करेगा। यूनियन के प्रतिनिधियों को भी यह सूचित कर दिया गया था कि उनकी मांगों को जांचा जाएगा और उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए इसे रखा जाएगा और यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान अनुबंध के समाप्त होने और नए अनुबंध के आरंभ होने के बीच कुछ अंतरवर्ती अवधि होगी और तब तक संभावित रूप से वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।

संबंधित पक्षों के सभी दावों और अभिलेख पर रखी सामग्री को पढ़ने के बाद: न्यायाधिकरण ने यह सूचित किया कि बैठक के कार्यवृत्त (अनुलग्नक आर-2) के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा उस अवधि हेतु खाद्यसामग्री भत्तों को दावा करना न्यायोचित नहीं है। जिस अवधि की खान-पान अनुबंध द्वारा कवर किया गया हो, बशर्त यथा सहमत रूप से खाद्यसामग्री को स्वीकार किया गया हो। वहीं इस बात का पता चला कि खान-पान कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा मानक से नीचे और घटिया गुणवत्ता की खाद्यसामग्री की आपूर्ति की गई, ऐसे में प्रतिवादियों का अनुबंध बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जलयान के मास्टर को चाहिए था कि मुद्दों की गंभीरता के बारे में प्रतिवादियों को सूचित किया जाता और अनुबंध के खण्ड-17 की शर्तों के अनुसार अनुबंध को निरस्त कर दिया होता। जलयानों के मास्टरों की ओर से प्रतिवादी को उचित रूप से अवगत न कराए जाने के कारण यह अनुबंध जारी रहा जिसकी तरह से उक्त विवाद सामने आया।

“ तथ्यों तथा परिस्थितियों को समझते हुए यह महसूस किया गया कि यदि पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी निष्कर्ष या निपटारे पर पहुंचे तो न्याय हो सकेगा।

“ 08.02.2012 को जब पूर्व सूचित अनुसूची के अनुसार कार्यवाही आरंभ हुई तब न्यायाधिकरण ने पक्षों को सलाह दी कि विवाद के लम्बित निर्णय पर वे सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वीकार्य समाधान करें। याचिकाकर्ता की ओर से लीगल प्रैक्टिसनर की उपस्थिति पर आर-4 द्वारा आपत्ति किए जान पर न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 150 को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात (अनुलग्नक पर) दोनों पक्षों द्वारा कोई आपत्ति न किए जान पर इन्हें अभिलेख में लिया गया और प्रदर्श के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा फाइल किए गए अनुलग्नक पी-1 से पी-15 के रूप में चिन्हित किया गया और चौथे प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में फाइल किए गए अनुलग्नक को प्रदर्श आर-1 से आर-7 के रूप में चिन्हित किया गया।

“ याचिकाकर्ता ने जिरह आरंभ की और इस का भाग पूरा किया। इस अवस्था में न्यायाधिकरण ने अगली सुनवाई अगले दिन के लिए तय कर दी ताकि पक्ष कोई संभावित समझौता कर सके।

“ 29.02.2012 को जब कार्यवाही आरंभ हुई तो याचिकाकर्ता ने निम्नोक्त रूप से अपने दावे को सीमित करने का प्रस्ताव रखा।

1) एम.वी.नॉनकवरी के संबंध में : दिनांक 01.03.2008 से 31.08.2008 तक कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 200 (दो सौ रुपए मात्र) और 01.09.2008 से 28.02.2009 तक की अवधि के लिए कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 405(चार सौ पाँच रुपए मात्र)

2) एम.वी.स्वराज दीप के संबंध में : यथा उपर्युक्त रूप से :

“ न्यायाधिकरण की सलाह पक्षों और संबंधित इच्छुक व्यक्तियों के बीच वे विचार-विमर्श और वार्ताओं के उपरांत पक्षों ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि वे इस बात पर परस्पर सहमत हैं कि कर्मीदल को निम्नोक्त रूप से खाद्यसामग्री के लिए भुगतान किया जाएगा और निवेदन किया कि उक्त शर्तों का अवॉर्ड पारित किया जाए।

1) एम.वी.नॉनकवरी के संबंध में : दिनांक 01.03.2008 से 30.11.2008 तक कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 200 (दो सौ रुपए मात्र) और 01.12.2008 से 28.02.2009 तक की अवधि के लिए कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 405(चार सौ पाँच रुपए मात्र)

2) एम.वी.स्वराज दीप के संबंध में : दिनांक 01.09.2008 से 30.11.2008 तक कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 200 (दो सौ रुपए मात्र) और 01.12.2008 से 28.02.2009 तक की अवधि के लिए कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 405(चार सौ पाँच रुपए मात्र)।

“ उपर्युक्त समझौते को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधिकरण ने एतद्वारा आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का दावा आंशिक रूप से अनुमत है और निम्नोक्त रूप से खाद्यसामग्री के लिए दो जलयानों के कर्मियों को भुगतान किया जाएगा:

1) एम.वी.नॉनकवरी के संबंध में : दिनांक 01.09.2008 से 30.11.2008 तक कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 200 (दो सौ रुपए मात्र) और 01.12.2008 से 28.02.2009 तक की अवधि के लिए कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 405(चार सौ पाँच रुपए मात्र)।

2) एम.वी.स्वराज दीप के संबंध में : दिनांक 01.09.2008 से 30.11.2008 तक कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 200 (दो सौ रुपए मात्र) और 01.12.2008 से 28.02.2009 तक की अवधि के लिए कर्मीदल के प्रति सदस्य को प्रतिदिन रु. 405(चार सौ पाँच रुपए मात्र)।

“ इस मामले की परिस्थितियों में खर्च का कोई आदेश नहीं होगा और पक्ष अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

हस्ताक्षर

(जी.वी.एल.सत्यकुमार,आईआरटीएस)  
एकल व्यक्ति न्यायाधिकरण

[फा.सं. सी-18018/1/2011-एमए]  
सुनील मिश्रा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

**S.O. 758(E).**—In pursuance of sub-section (5) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby publishes an Award of the Tribunal constituted under the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping under S.O. No. 505 (E) dated the 31<sup>st</sup> of May, 2011 to adjudicate the charter of demands submitted to the Lt. Governor and other in the writ petition No. 1276 of 2010 by the National Union of Seafarers of India, Port Blair verses Lt. Governor, Andaman & Nicobar island and others.

### A W A R D

On receipt of the notification of the Ministry of Shipping, Govt. of India, issued vide S.O. No. 1250 (E) dated 31/05/2011 in pursuance of the orders of the Hon'ble High Court of Judicature at Calcutta (Circuit bench at Port Blair) dated 19/11/2010 in W.P. No. 1276/2010, the One Person

Tribunal has been set up and started functioning from 11/08/2011 and all the parties concerned were duly informed about the same along with the schedule of proceedings.

The petitioner M/s. N.U.S.I. represented by its branch representative Mr. Dhavinder Ram submitted its claim duly serving the copies of the same on the respondents.

The fourth respondent on its behalf and on behalf of other three respondents filed the reply to the claim duly serving a copy of the same on the petitioner.

On examining the claim and the counter/reply together with the annexures being relied on by the parties, the tribunal has identified the following issues to be adjudicated.

1. Whether the crews are justified in going ahead with the self-messing arrangement without the approval of the competent authority.
2. Whether the National Maritime Board agreement dated 14/02/2008 to which the respondents are not signatories, can be enforced against the respondents.
3. Whether the NMB agreement is providing for self-messing arrangement by the crews in any circumstances.
4. Whether the respondents are justified in extending the contract of catering services beyond August 2008 in spite of the complaints by the petitioner on the quality of the provisions and food being provided on the vessels.
5. Whether the crew on the two vessels viz M.V. Nan Cowry & M.V. Swaraj Dweep are entitled for the victual allowance for the periods 01/03/2008 to 28/02/2009 and 01/09/2008 to 28/02/2009 in the absence of any express agreement or approval of the same by the competent authority.

As could be evidenced from the material on record there were no complaints on the quality of the provisions and food provided on board the vessel M.V. Nan Cowry to the crew prior to 18/01/2008 (as per annexure P-2). The agreement of catering commenced from 14/09/2007 and expires on 13/09/2008 (as per annexure P-1). Similarly there were no complaints from the crew of the vessel M.V. Swaraj Dweep prior to 22/07/2008. It is evident from Annexure P-5 i.e. Abstract from official log book of M.V. Nan Cowry) that on the complaint of the crew, the Master in the presence of others on board, inspected the provisions on 29/02/2008 and found to be of bad quality and unfit for human consumption and issued necessary instructions to remove all the bad provisions and also observed that such instructions were also issued earlier to the Canteen Manager failed to obey the same. Further on 01/03/2008 when the crew informed the Master that they will not take any provisions from the canteen manager and that they would manage their affairs themselves. The master stated that he could only ensure issuance of good provisions to them and accepting or not accepting is their choice and he assured to inform the respondent. Further during the rounds of the Master on the

same day on board he observed that items like Arar dal, salt etc. were of poor quality and catering officer was instructed to remove all poor quality and expired items from the store.

From Annexure P-6 it is understood that the Master of M.V. Swaraj Dweep forwarded a copy of the official log entry Dt. 12/03/2008 to the 4th respondent. As could be seen from the said abstract of the official log book of M.V. Swaraj Dweep no specific observations were found on the quality but all the crew members with their heads of departments at the bridge-wing requested for self messing as they are not satisfied with the existing arrangements.

Annexure P-7 is the NMB Agreement which contained the issue of on board self messing apart from various other issues relating to the service conditions, allowances etc., in the said agreement clause 28 provides for messing allowance where the self messing arrangement existed but it has not provided for or contained anything on the right of the crew to choose for self messing.

The 4th respondent in the counter emphasized that crew members on board the vessel were receiving the provisions of food articles as per NMB Agreement, 2000 but none of the party placed the same before the Tribunal to understand the prevailing terms and conditions of service. It was emphasized that as the competent authority has approved the self-messing system on board only w.e.f. 01/03/2009 they are justified in making the revised payments (victual allowance) from 01/03/2009 and the petitioner cannot claim for any period prior to the approved date.

Annexure R-2 which is the Minutes of the Meeting 08/08/2008 held on the subject issue is very vital, wherein the Petitioner the catering contractors and also the officials of Respondent were present. It reveals that the representatives of the Union unanimously opined that self-messing should be allowed w.e.f 01/09/2008, i.e. immediately after expiry of the present contract. It was also agreed that the representatives of the Union shall accept the provisions as per quantity and quality notified and the contractor agreed to supply the provisions for the pending period as per Notification. The representatives of the Union were also informed that their demands shall be examined and put to the higher authorities for a final decision and it was also informed that there will be some transition period between expiry of the present contract and execution of fresh contract and till such time the present system is likely to continue.

Having gone through all the contentions of the respective parties and the material brought on record : the Tribunal felt that in the light of the Minutes of the Meeting (Annexure R -2) the petitioner is not justified in claiming the victual allowances for the period covered by the catering contract if the provisions were accepted as agreed. On the other hand having come to know about the supply of substandard and poor quality provisions by the catering contractors the Respondents ought not have extended the contract. Further the Master of the vessel ought to have kept the respondents informed about the seriousness of the issues and should have got the contract cancelled in terms of Clause 17 of

the Contract. As a result of the failure on part of the Masters of the vessels in appraising the respondent properly the contract was continued which resulted the subject dispute.

Having regard to the facts and circumstances it is felt that the ends of justice could be met if the parties could arrive at a conclusion or settlement amicably.

On 28/02/2012 when the proceedings commenced as per the schedule intimated earlier the Tribunal advised the parties to work out amicably on an acceptable solution pending adjudication of the dispute. On the objection raised by the R-4 on the presence of legal practitioner on behalf of the petitioner the Tribunal ordered the petitioner to present the case in person keeping in view Sec. 150 of Merchant Shipping Act, 1958. Both the parties did not raise any objection on the material papers (Annexures) filed by the respective parties hence the same were taken on record and marked as Exhibits. Annexure P-1 to P-15 filed by the petitioner were marked as Exhibits P-1 to P-15 and Annexure filed in support of the reply by 4<sup>th</sup> respondent were marked as Exhibits R-1 to R-7.

The petitioner commenced the arguments and completed in part. At this stage the Tribunal has adjourned the further hearing to the next day to facilitate the parties to arrive at any possible compromise.

On 29/02/2012 when the proceedings commenced, the petitioner offered to limit its claim as follows:

- 1) **In respect of M.V. Nan Cowry :** Rs. 200/ (Rupees two hundred only) per a day per crew member from 01/03/2008 to 31/08/2008 and Rs. 405/- (Rupees four hundred and five only) per a day per crew member for the period 01/09/2008 to 28/02/2009.
- 2) **In respect of M.V. Swaraj Dweep :** Same as above.

Upon the advise of the Tribunal, after deliberations, negotiations between the parties and the respective interested persons, the parties have finally informed the Tribunal that they have mutually agreed that the crew shall be paid for the provisions as follows and requested to pass an award the said terms.

- 1) **In respect of M.V. Nan Cowry :** Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per a day per crew member from 01/03/2008 to 30/11/2008 and Rs. 405/- (Rupees four hundred and five only) per a day per crew member for the period 01/12/2008 to 28/02/2009.
- 2) **In respect of M.V. Swaraj Dweep :** Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per a day per crew member from 01/09/2008 to 30/11/2008 and Rs. 405/- (Rupees four hundred and five only) per a day per crew member for the period 01/12/2008 to 28/02/2009.

In view of the above compromise the Tribunal hereby ordered that the claim of the petitioner is allowed partly and the crew of the two vessels shall be paid for the provisions as follows:

1) **In respect of M.V. Nan Cowry** : Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per a day per crew member from 01/03/2008 to 30/11/2008 and Rs. 405/- (Rupees four hundred and five only) per a day per crew member for the period 01/12/2008 to 28/02/2009.

2) **In respect of M.V. Swaraj Dweep** : Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per a day per crew member from 01/09/2008 to 30/11/2008 and Rs. 405/- (Rupees four hundred and five only) per a day per crew member for the period 01/12/2008 to 28/02/2009.

In the circumstances of the case there shall be no order for costs and the parties shall bear their respective costs.

Sd/-

(G.V.L. SATYA KUMAR, IRTS)  
One Person Tribunal

[File No. C-18018/1/2011-MA]

SUNIL MISHRA, Jt. Secy.